बैड बैंक

drishtiias.com/hindi/printpdf/bad-bank-5

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India)** के गवर्नर एक **बैड बैंक** (Bad Bank) बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

बैड बैंक के विषय में:

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- तकनीकी रूप से बैड बैंक एक **परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी** (Asset Reconstruction Company- ARC) या **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और समय के साथ धन की वसूली करती है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है।
- अमेरिका स्थित **मेल्लोन बैंक** (Mellon Bank) द्वारा वर्ष 1988 में पहला बैड बैंक बनाया गया था, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्राँस और जर्मनी सहित अन्य देशों ने इस अवधारणा में अपनाया।
  - अमेरिका में इसके लिये **तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम** (Troubled Asset Relief Programme- TARP) व्यवस्था की गई है।
  - आयरलैंड में वित्तीय संकट से उभरने के लिये वर्ष 2009 में **राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन एजेंसी (National Asset Management Agency)** की स्थापना की गई थी।

बैड बैंक की भारत में ज़रूरत:

- **आर्थिक सुधार हेतु:**
  RBI ने आशंका जताई है कि बैंकिंग क्षेत्र में महामारी के कारण बैड ऋणों में वृद्धि हो सकती है।

- **सरकारी सहायता:**
  - निजी उधारदाताओं द्वारा वित्तपोषित और सरकार द्वारा समर्थित व्यावसायिक रूप से संचालित बैड बैंक, **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों** (Non-Performing Asset) से निपटने के लिये एक प्रभावी तंत्र हो सकता है।
  - इस बैंक में सरकार की भागीदारी को बैड ऋण से निपटने की प्रक्रिया को तेज करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
- **बढ़ता NPA:**
  - **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report):** RBI ने आपनी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का सकल NPA सितंबर 2020 की तुलना में 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में 13.5% तक हो सकता है।
  - **के वी कामथ कमेटी:** भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के बाद 15.52 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ के कारण तनाव की स्थिति देखी जा रही है, हालाँकि इस क्षेत्र पर महामारी के पहले से ही 22.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ था।
    - समिति ने कहा कि खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, सड़क और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
    - कोविड महामारी से पहले से ही तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** (Non-Banking Financial Company), बिजली, स्टील, रियल एस्टेट और निर्माण शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** वित्तीय प्रणाली में तनाव की समस्या से निपटने के लिये कई अन्य देशों ने संस्थागत तंत्र की स्थापना की थी।

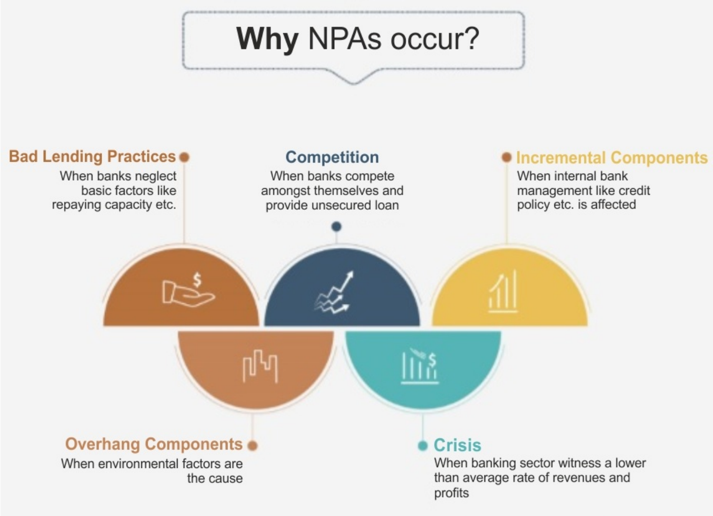
Why NPAs occur?
Bad Lending Practices
When banks neglect basic factors like repaying capacity etc.
Competition
When banks compete amongst themselves and provide unsecured loan
Incremental Components
When internal bank management like credit policy etc. is affected
Overhang Components
When environmental factors are the cause
Crisis
When banking sector witness a lower than average rate of revenues and profits

चुनौतियाँ:

- **गतिशील पूंजी:**

  महामारी-ग्रस्त अर्थव्यवस्था में बैड संपत्ति के लिये खरीदारों को ढूँढ़ना एक चुनौती होगी, खासकर जब सरकारें राजकोषीय घाटे के मुद्दे का सामना कर रही हैं।

- **अंतर्निहित मुद्दे की अनदेखी:**
  - शासनिक सुधारों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कुल NPA में से 86% के लिये ज़िम्मेदार हैं) अतीत की तरह व्यवसाय कर सकते हैं और बैड ऋणों को समाप्त कर सकते हैं।
  - बैड बैंक का विचार सरकारी जेब (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से दूसरे (बैड बैंक) को ऋण स्थानांतरित करने जैसा है।
- **पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से निपटने का प्रावधान:**
  - केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।
  - बैड बैंक की अवधारणा का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बैंकों की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिये पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है, इसलिये बैड बैंक की आवश्यकता नहीं है।
- **बाज़ार से संबंधित मुद्दे:**

  वाणिज्यिक बैंकों से बैड बैंक में बैड संपत्ति का स्थानांतरण बाज़ार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- **नैतिक जोखिम:**

  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि बैड बैंक NPA को कम करने की प्रतिबद्धता के बिना एक नैतिक खतरा पैदा कर सकता है और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार को जारी रख सकता है।

पूर्व के प्रस्ताव:

- **भारतीय बैंकों के संघ** (Indian Banks' Association) के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र ने सरकार और बैंकों से निष्पक्ष (Equity) योगदान का प्रस्ताव करते हुए NPA समस्या के समाधान के लिये एक बैड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- आर्थिक सर्वेक्षण, 2017 में भारतीय बैंकों से उच्च मूल्य के NPA खरीदने के लिये **सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी** (Public Sector Asset Rehabilitation Agency- PARA) का सुझाव दिया गया है।

आगे की राह

- **समग्र सुधार:**

  जब तक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेगा तब तक उनके व्यवसाय में घाटे की स्थिति बनी रहेगी और उनके द्वारा मितव्ययी (Prudential) मानदंडों के आधार पर उधार दिया जाना जारी रहेगा। इसलिये एक बैड बैंक की स्थापना के बारे में बहस को बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों के उचित कार्यान्वयन से पहले किया जाना चाहिये, जैसा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई **इंद्र धनुष** (Indra Dhanush) योजना के तहत परिकल्पित था।

- **टेलर मेड अप्रोच:**
  यह एक चुनौती है जिसे कई मोर्चों पर सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ बैड बैंक की स्थापना कर देना सुधार के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद **बैड लोन की समस्या का समाधान टेलर मेड अप्रोच** (Tailor Made Approach) **के माध्यम से करना** और बैड बैंक का उपयोग अन्य सभी तरीकों के असफल होने पर ही अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
